

## उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 03/2011-12

जेठा हेम्ब्रम .....अपीलकर्ता  
 बनाम  
 मिश्रा सोरेन, प्रधान एवं अन्य .....उत्तरकारी

### ॥ आदेश ॥

26/04/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 03/2011-12 जेठा हेम्ब्रम बनाम मिश्रा सोरेन, प्रधान एवं अन्य, मौजा बाघमारा, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 70/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

उत्तरकारी काफी समय से न्यायालय में अनुपस्थित है। फलतः उनके ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा के दाग सं0 237 गत सर्वे सेटेलमेंट में गड़हा बोलकर दर्ज है। अपीलकर्ता द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त जमीन का बन्दोबस्ती हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा भी उनके साथ बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर अस्वीकृत किया गया कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 27 एवं 28 में गड़हा बोलकर दर्ज जमीन को बन्दोबस्ती करने का कही स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

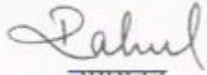
इसपर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त जमीन को धानी के रूप में खंडित किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा भी बन्दोबस्ती का अनुशंसा किया गया है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 36 में गड़हा बन्दोबस्ती पर किसी प्रकार मनाही (Debar) नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलकर्ता के आवेदन स्वीकारणीय है।

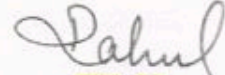
निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध कागजातों एवं अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी द्वारा उक्त जमीन को अपीलकर्ता के साथ बन्दोबस्ती करने का अनुशंसा किया गया है। उन्होंने यह भी अंकित किया है कि अपीलकर्ता को अपनी निजी जमीन 12 बीघा 02 कठ्ठा है निम्न न्यायालय में उत्तरकारी द्वारा दाखिल आपत्ति आवेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत जमीन तत्कालीन प्रधान गौरा सोरेन द्वारा 22 बैशाख 1359 बंगला साल में लूधिया सोरेन के साथ पट्टा बन्दोबस्ती किया है एवं

उनके द्वारा उक्त जमीन को खंडित कर जोत आबाद किया जा राह है किन्तु उनके द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन गत सर्वे में गडढा बोलकर दर्ज है। सं०प० काश्तकारी अधिनियम में सिर्फ परती/फौती जमीन की ही बन्दोबस्ती का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में गडढा की बन्दोबस्ती की स्वीकृति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

  
उपायुक्त,  
दुमका।

  
उपायुक्त,  
दुमका।